प्रकाशनार्थ

पटना, 19 अक्तूबर। आज आद्री और इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर (आइजीसी) द्वारा ''भारत में कृषि आपूर्ति श्रृंखला पर कोविड-19 के प्रभाव का मार्गनिर्देशन'' शीर्षक वेबिनार का आयोजन किया गया। आद्री के सदस्य सचिव डॉ. शैबाल गुप्ता ने पैनल में शामिल लोगों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम का आरंभ किया। चर्चा में भाग ले रहे पैनलिस्ट बिहार के कृषि विभाग के सचिव श्री एन. श्रवण कुमार, भारतीय अंतराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के अवकाशप्राप्त सीनियर फेलो और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के पूर्व सचिव जनाब सीराज हसन, तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनस के सहायक प्रोफेसर श्री शेखर तोमर शामिल थे। चर्चा का संचालन अशोका विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर मेखला कृष्णमूर्ति ने किया।

चर्चा का आरंभ करते हुए **डॉ. शैबाल गुप्ता** ने कहा कि ''स्वास्थ्य आपदा के रूप में जारी कोविड-19 ने जीवन के सारे आयामों को प्रभावित किया है। इस आपदा में लोगों की जिंदगी बचाना और अग्रणी सुविधाएं उपलब्ध कराना अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनो की प्राथमिकता है। इस स्वास्थ्य आपदा से दोनो ही सरकारें मुस्तैदी से निपट रही हैं। लेकिन इसी के कारण 24 मार्च से 31 मई तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन हुआ जिसके चलते कृषि-आहार आपूर्ति श्रृंखला में भारी व्यवधान आया। योजनाविहीन और नीति संबंधी अचानक के झटकों ने उत्पादन से लेकर खरीद और प्रसंस्करण, परिवहन और लॉजिस्टिक्स तथा मांग – आपूर्ति श्रृंखला के सारे हिस्सों को प्रभावित किया। हालांकि सिद्धांत रूप में राष्ट्रव्यवापी लॉकडाउन में 'आवश्यक' वस्तुओं की आवाजाही को छूट मिली हुई थी और आहार संबंधी बाजारों आबाध रूप से काम करने दिया गया, लेकिन वास्तव में कृषि उत्पादों की थोक मंडियों के बंद होने तथा राज्य की सीमा पर और शहरों के अंदर वाहनों पर प्रतिबंध और उनमें व्यवधान होने से कृषि आपूर्ति श्रृंखला को बड़े पैमाने पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जमीन स्तर से प्राप्त आरंभिक प्रमाणों से पता चलता है कि सामग्रियों के लिए लॉकडाउन लागू होने के बाद पहले की तुलना में मंडियों में आवक 42 प्रतिशत घट गई।''

श्री **एन. श्रवण कुमार** ने बताया कि ''बिहार प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य है लेकिन दुर्भाग्यवश, कोविड-19 के दौरान मक्का की कीमत में 50 प्रतिशत गिरावट आ गई। इससे स्टार्च उद्योग भी प्रभावित हुआ जिसके कारण मक्का की मांग में कमी आई। छोटे और सीमांत किसानों को तत्काल नगद की जरूरत थी इसलिए कोविड के दौरान आपदा बिक्री देखी गई क्योंकि मक्का के खरीद की कोई और व्यवस्था नहीं थी। मंदिरों के बंद होने के कारण मांग घटने से फूलों की खेती भी प्रभावित हुई। इसका असर गेंदा की खेती पर पड़ा जिसे अधिकांशतः लीज या बंटाई पर खेती करने वाले लोगों द्वारा उपजाया जाता है। जिन किसानों का बाजार कोविड के दौरान प्रभावित हुआ है, उनको सब्सिडी तथा अन्य मामलों में बिहार सरकार ने प्राथमिकता दी है।'' साथ ही, उन्होंने दूध उत्पादन का प्रमुखता से उल्लेख किया। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से दूध की खरीद में 20 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई। कोविड संकट ने दर्शाया है कि बाजार में कीमत का पता लगाने, ई-नैम और किसानों के लिए बाजार संबंधी सहायता देने में सूचना प्रौद्योगिकी बड़ी भूमिका निभाती है। आगे हमारा लक्ष्य खाद्य उत्पादक संगठनों या खाद्य उत्पादक कंपनियों के जरिए किसानों को एक साथ

लाना है, इसीलिए हमने अग्रवर्ती और पृष्ठवर्ती कड़ियों में छोटी जोत वाले किसानों को लगातार सहायता देने के लिहाज से बिहार लघु कृषक कृषि कंसॉर्टियम का गठन किया है।

वहीं, सीराज हसन ने बताया कि इस वर्ष अधिक समय तक जाड़ा पड़ने के कारण मार्च में फसलों की कटनी में विलंब होने के बावजूद, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश की खरीद व्यवस्था ने इस वर्ष बहुत ही अच्छा काम किया। इन राज्यों का प्रशंसनीय काम गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक खरीद से भी व्यक्त हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा कि कृषि बाजार पोर्टल पर मौजूद आंकड़ों का उनकी गुणवत्ता के लिहाज से सावधानी से अध्ययन और विश्लेषण करने की जरूरत है।

इसी प्रकार, शेखर तोमर का कहना था कि ''हम देखते हैं कि बाजार से दूर उत्पादित कृषि उत्पादों की मंडियों में आवक 40 प्रतिशत घट गई। यह भी दिखता है कि फल और सब्जियों जैसे शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों की ढुलाई में व्यवधान आ जाने के कारण खेतों से थालियों तक पहुंचने की स्थिति में सुधार नहीं हो पाता है। ऐसी अनिश्चित स्थितियों से निपटने के मामले में स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।''

मेखला कृष्णमूर्ति ने कहा कि बाजार के नजरिए, कीमत पर चर्चा और केंद्र तथा राज्य की प्रभाविता के दृष्टिकोण से समझने के लिहाज से यह चर्चा बहुत समृद्ध है। निष्कर्ष यह है कि कृषि क्षेत्र के लिए निवेश, नवाचार और संस्था निर्माण तथा दृष्टि निर्माण करना अब राज्यों पर निर्भर करता है।

समापन वक्तव्य आद्री के निदेशक प्रोफेसर प्रभात पी. घोष ने दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान महामारी जैसे दौर में और कृषि विधेयक 2020 की हाल में की गई घोषणा जैसी स्थितियों में भारत में कृषि आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे पर आवश्यक संवाद करने की गुंजाइश बनाना सबसे जरूरी हो गया है।

(Anjani Kumar Verma)